

विधानसभा अतारंकित प्रश्न क्रमांक 6885
द्वारा माननीय विधायक - श्री शंकरलाल तिवारी

रीवा संभाग में विगत 03 वर्षों (01.01.2014 से 31.12.2016) तक पकड़े गये प्रकरणों की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	01.01.2014 से 31.12.2016 तक की अवधि में अवैध उत्खनन के दर्ज प्रकरणों की संख्या	दर्ज प्रकरणों में से निराकृत प्रकरणों की संख्या	निराकृत प्रकरणों में आरोपित अर्थदण्ड (लाख रुपये में)	आरोपित अर्थदण्ड में से अब तक वसूल की गई अर्थदण्ड की राशि (लाख रुपये में)	लंबित प्रकरणों की संख्या
1	रीवा	63	14	9.87	9.87	49
2	सतना	72	अनिराकृत	निरंक	अनिराकृत	72
3	सीधी	22	05	10129.80	0	17
4	सिंगरौली	28	08	13.61	3.57	20

अनुभवा अधिवक्ता
साध्यविशेष शाखा, जल,
खानिज, सार्वजनिक विभाग

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 6885
द्वारा माननीय विधायक - श्री शंकरलाल तिवारी

जिले में अवैध उत्खनन रोकने के लिये क्या-क्या कार्यवाही की गई

क्र.	जिले का नाम	जिले में अवैध उत्खनन को रोकने के लिये जिला प्रशासन द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई संक्षेप में विवरण दिया जाये	रिमांक
1	रीवा	अवैध उत्खनन को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स कमेटी एवं खनिज विभाग द्वारा समय-समय औचक निरीक्षण किया जाकर जिले में विगत तीन वर्षों में अवैध उत्खनन के 63 प्रकरण दर्ज किये गये है। दर्ज प्रकरणों को निराकरण हेतु सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अवैध उत्खनन के दर्ज 63 प्रकरणों में से निराकृत 14 प्रकरणों में अर्थदण्ड राशि रुपये 9,87,000/- वसूल की गई है।	-
2	सतना	अवैध उत्खनन को रोकने के लिए जिला प्रशासन सतना द्वारा राजस्व, खनिज, वन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं पुलिस विभाग को सम्मिलित कर शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिलास्तरीय टास्क फोर्स की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार संयुक्त रूप से कार्यवाही की जाती है एवं प्रत्येक अनुविभाग में अवैध उत्खनन की रोकथाम के लिए दल गठित किये गये है। अवैध उत्खननकर्ताओं पर सतत निगरानी की कार्यवाही की जाती है।	-
3	सीधी	अवैध उत्खनन को रोकने के लिये जिले में टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया है, जिसमें हर माह में बैठक आयोजित कर वन, राजस्व, पुलिस एवं खनिज विभाग द्वारा अवैध उत्खनन/परिवहन की जांच की जाती है।	
4	सिंगरौली	अवैध उत्खनन को रोकने के लिये प्रशासन द्वारा जिले स्तर पर गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स के माध्यम से सम्पूर्ण क्षेत्र पर सतत निगरानी रखी जा रही है तथा अवैध उत्खनन/परिवहन एवं भण्डारण करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाती है। प्रत्येक माह टाक फोर्स की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसमें की गई कार्यवाही की समीक्षा के साथ-साथ आगामी माह हेतु रणनीति तैयार की जाती है।	-

अनुमोदित अधिकारी
सहायक जिला प्रशासक,
खनिज, वन व पर्यावरण विभाग